मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा चतुर्दश सत्र

फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023

(8 फाल्गुन, शक संवत् 1944)

[खण्ड- 14] [अंक-1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023

(8 फाल्गुन, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

<u>राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूह गान</u>

अध्यक्ष महोदय - अब, राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूह गान किया गया.)

अब, सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

11. 12 बजे

(राज्यपाल महोदय का सदन में चल समारोह के साथ आगमन हुआ.)

11.13 बजे **<u>राज्यपाल महोदय का अभिभाषण</u>**

राज्यपाल महोदय(श्री मंगुभाई पटेल)-- सभी को नमस्कार,

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।

2. पन्द्रहवीं विधानसभा के पाँचवें और अंतिम बजट सत्र में सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। यह निश्चय ही गर्व एवं सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अमृत-महोत्सव से लेकर अमृत-काल तक समृद्ध, विकसित एवं आत्म-निर्भर भारत के निर्माण की एक नई महायात्रा प्रारम्भ हो गई है। मध्यप्रदेश भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों एवं संकल्पों की सिद्धि में अपना हर सम्भव योगदान दे रहा है।मेरी सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है और प्रतिबिम्ब भी ।

3. आज़ादी के अमृत-काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जी-20 समूह की अध्यक्षता वैश्विक परिदृश्य में भारत के स्वर्ण- युग की शंख-ध्वनि है।

"एक धरती - एक परिवार - एक भविष्य" की थीम जी-20 को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भारतीय दर्शन की आभा से आलोकित कर रही है। मध्यप्रदेश को जी-20 समूह की 8 बैठकों की मेज़बानी का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब तक 3 बैठकें क्रमश: भोपाल, इंदौर और खजुराहो में आयोजित हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से मध्यप्रदेश की छवि पूरी दुनिया में उज्ज्वल हुई है।

4. मध्यप्रदेश की धरती पर आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान 70 से अधिक देशों से आए 3 हजार 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में निर्मित 'नमो ग्लोबल गार्डन' प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाए गए पौधों के रूप में आयोजन की सुखद स्मृतियों को चिरकाल तक जीवंत बनाए रखेगा।

5. मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है- मध्यप्रदेश की जनता की जिन्दगी को बदलना । प्रदेश के गाँव - गाँव और शहर - शहर में निकाली गई विकास यात्राएँ सच्चे अर्थों में जनसेवा का महायज्ञ बन गई हैं। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते विकास-रथ के साथ विकास-पताका हाथ में लिए जनता उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में शामिल हुई।

दिनांक 05 फरवरी से प्रारम्भ विकास यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया है। विकास यात्रा ने जनता की यात्रा के रूप में सफलता और रचनात्मकता के नए आयाम स्थापित किये हैं।

6. मेरी सरकार अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रही है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए का व्यय कर 8 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण तथा 69 पुलों का निर्माण किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत 17 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। रीवा-सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल के निर्माण ने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी है। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाइवे मध्यप्रदेश की तस्वीर को बदलकर रख देंगे।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे और विंध्य एक्सप्रेस-वे, समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी, रीवा में एयरपोर्ट निर्माण तथा ग्वालियर में विमानतल के विस्तार और विकास से आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने साकार होंगे।

7. मेरी सरकार गाँव-गाँव में और खेत-खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब तक 45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन 475 सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। नर्मदा कछार की 24 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता वाली 12 परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाहियाँ प्रारंभ हो गई हैं। रुपए 44 हजार 600 करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

8. प्रदेश में ऊर्जा अधोसंरचना, आत्म-निर्भरता की परिचायक है और अंत्योदय की भी। हमारी समेकित ऊर्जा क्षमता 28 हजार मेगावाट से भी अधिक हो गई है।

मेरी सरकार द्वारा अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति के पात्र कृषकों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना तथा कुसुम योजना के माध्यम से घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 लागू की गई है। प्रदेश में 2 हजार 850 मेगावाट की सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क तथा पवन एवं सोलर हाईब्रिड परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। ऊर्जा साक्षरता अभियान से 12 लाख से अधिक नागरिकों को जोड़ा गया है।

9. अधोसंरचना निवेश के साथ औद्योगिक निवेश के संगम से चहुँमुखी विकास मेरी सरकार का मंत्र है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 मध्यप्रदेश के लिए अभूतपूर्व रही है। देश-विदेश से प्रदेश में 15 लाख 42 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों एवं शासन तंत्र पर निवेशकों के अटूट भरोसे का ही परिणाम है। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 29 लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र और 2 आई.टी. पार्क के विकास और 16 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन का कार्य लगभग 2 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है ।

रतलाम, पीथमपुर एवं देवास में नए निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में मेडिकल डिवाइस उत्पादन इकाइयों की स्थापना प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में 1 हजार 400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है ।

10. प्रदेश में 22 MSME क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5 हजार 400 करोड़ रुपए का निवेश और 50 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन संभावित है। मध्यप्रदेश को देश का स्टार्ट-अप हब बनाने के लक्ष्य के साथ स्टार्ट-अप नीति-2022 लागू करते हुए ऑनलाईन पोर्टल एवं स्टार्ट-अप सेन्टर की स्थापना की गई है। इन्दौर के सुपर कॉरिडोर में 22 एकड़ ज़मीन पर 35 मंजिला स्टार्ट-अप पार्क निर्मित किया जाएगा, जिससे 20 हजार रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। मध्यप्रदेश के हथकरघा वस्त्रों के फैशन शो इन्दौर और मुम्बई फैशन वीक से लेकर न्यूयार्क फैशन वीक तक अपनी छाप छोड़कर आए हैं। प्रदेश के रेशम उत्पादक किसानों को ककून का उचित मूल्य दिलाने के लिए नर्मदापुरम जिले में ककून मण्डी प्रारंभ की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।

11. माननीय प्रधानमंत्री जी के "सस्टेनेबल एग्रीकल्चर" के मंत्र को मेरी सरकार ने अपना मिशन बनाया है। कृषि का विविधीकरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नवीनतम तकनीकों का उपयोग, स्वाईल हेल्थ पर विशेष ध्यान, नरवई जलाने की प्रथा का हतोत्साहन एवं किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है। मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023 में मिलेट मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

12. मेरी सरकार प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए सुनियोजित रणनीति के साथ काम कर रही है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में किसानों को 32 हजार 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अल्पावधि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराए गए हैं। गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे - पर्यटन,

ग्रामीण परिवहन, सेवा प्रदाय, आई.टी., सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी, श्रम, भण्डारण, जैविक कृषि, गणवेश, सुरक्षा, महिला गृह उद्योग, कला, स्वास्थ्य, कौशल उन्नयन, मुर्गी पालन, तकनीकी शिक्षा आदि में भी 800 से अधिक नवीन सहकारी संस्थाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। सहकारी क्षेत्रों में 43 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत किए गए हैं।

13. मेरी सरकार कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों में किसानों की समृद्धि के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 3 लाख 64 हजार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत अब तक 447 डेयरियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। पशुपालकों को घर पहुँच पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 400 से अधिक चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़कर दोगुना हो गया है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश को देश में विशेष श्रेणी का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है।

प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना के अंतर्गत 1 लाख 17 हजार से अधिक मछली पालकों का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कराया गया है। साथ ही 66 हजार 400 से अधिक मछली पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं।

14. उद्यानिकी क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्वालियर में आलू एवं बेकरी आधारित उत्पाद, मुरैना में सरसों एवं मिलेट आधारित उत्पाद तथा सीहोर में अमरूद एवं अन्य फल आधारित प्रोसेस्ड उत्पादों हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत के इन्क्यूबेशन सेन्टर्स स्थापित किए जा रहे हैं। बाग-बगीचों में कार्य कर रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए 2 हजार 500 युवक-युवतियों को माली बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ग्वालियर में 10 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक नर्सरी स्वीकृत हुई है।

15. मेरी सरकार प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर सबके कल्याण और विकास के लिए दिन-रात एक कर रही है। सरकार का संकल्प गरीबी की तस्वीर और गरीबों की तकदीर बदलना है। संबल योजना, संबल 2.0 एवं भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाएँ 1 करोड़ 71 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों के जीवन का संबल है।

16. प्रदेश के 5 करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य करने का अवसर प्रदेश के युवाओं को देने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना स्वीकृत की गई है। नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे 100 दीनदयाल रसोई केन्द्रों पर आम-जनता को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है।

17. मेरी सरकार गरीबों, दिव्यांगजन, वृद्धजन, निराश्रितों, कल्याणी बहनों, परित्यक्ताओं, अविवाहिताओं एवं उभयलिंगी व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है तथा उन्हें पात्रतानुसार हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर-2022 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशव्यापी नशामुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए प्रदेश में 75 वरिष्ठ आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत 5 हजार से अधिक दिव्यांगजन को 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

18. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के माध्यम से प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरूआत हुई है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अब तक 40 हजार से अधिक परिवारों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के माध्यम से 47 लाख 55 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 39 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 58 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत कर 56 लाख 70 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों तक नल का शुद्ध जल पहुँचाया जा चुका है।

19. मेरी सरकार सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक समावेशन को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। दिनांक 15 नवम्बर-2022 की तिथि मध्यप्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है। इस दिन "जनजातीय गौरव दिवस" के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से प्रदेश की धरती पर "पेसा नियम-2022" लागू हो गए।

इन नियमों ने राज्य के 20 जनजातीय बहुल जिलों के जनजातीय भाई-बहनों को जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मामलों में अधिकार संपन्न, संसाधन संपन्न और शक्ति संपन्न बना दिया है। पेसा नियमों के अंतर्गत 268 ग्रामसभाओं द्वारा तेन्दूपत्ता के संग्रहण एवं विपणन स्वयं करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

20. वर्ष 2021-22 में आज़ादी का अमृत महोत्सव जनजातीय जननायकों के अमर बलिदानों की गौरव गाथाओं से प्रदेश को आलोकित करता रहा। मेरी सरकार ने भारत माँ की गुलामी से मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों की स्मृति में स्मारकों एवं संग्रहालयों का निर्माण कराया है। रानी कमलापति एवं क्रांतिसूर्य टंट्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशनों का, राजा शंकरशाह के नाम पर छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय का एवं भगवान बिरसा मुण्डा एवं राजा हृदयशाह के नाम पर मेडिकल कॉलेजों का नामकरण सरकार की ओर से इन महानायकों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है।

21. मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में नियमित रूप से राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है।

जनजातीय बहुल जिलों - धार, बालाघाट, मण्डला एवं श्योपुर के साथ ही भिण्ड जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। सिकलसेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन अब सभी 89 जनजातीय विकासखण्डों में लागू कर दिया गया है। भारत सरकार की नई प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 7 हजार 300 से अधिक जनजातीय बहुल ग्रामों में विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा रहा है। आहार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति की महिलाओं को प्रति वर्ष 285 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए जा रहे हैं।

22. जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा एवं कौशल विकास की दिशा में मेरी सरकार के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। आकांक्षा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 से अधिक विद्यार्थी नि:शुल्क कोचिंग का लाभ लेकर नीट, क्लेट और जे.ई.ई. की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अपनी उच्च शिक्षा को निरंतर रखने के लिए 1 लाख 26 हजार से अधिक जनजातीय बालक-बालिकाओं को इस वर्ष आवास सहायता योजना का लाभ दिया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 5 कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।

23. मेरी सरकार प्रदेश में समतामूलक समाज का निर्माण कर रही है। इसी अनुक्रम में 100 करोड़ रुपये की लागत से समरसता के संत पूज्य रविदास जी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। स्मारक परिसर में संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व, दोहे एवं शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। विगत लगभग 3 वर्षों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ वितरित किए गए हैं।

24. मेरी सरकार प्रदेश के पिछड़े वर्गों को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ स्थानीय निर्वाचन इन वर्गों के विकास और कल्याण के मार्ग पर मील का पत्थर है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना तथा स्व-रोज़गार योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से 6 हजार उद्यमों तथा 30 हजार स्व-रोज़गार सृजन हेतु सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को विदेश में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना भी प्रारंभ कर दी गई है।

25. मेरी सरकार ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के लिए रोज़गार सृजन का एक अभिनव प्रयास करते हुए विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्व-रोज़गार योजना लागू की है। इन समुदायों के लिए रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन समुदायों की संस्कृति, ज्ञान, कला और परंपराओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इन्दौर में एक विशिष्ट संग्रहालय बनाने की योजना है।

26. मेरी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों और बच्चों की जिंदगी को सँवारने के अनुष्ठान को अभूतपूर्व आयाम दिए हैं। राज्य सरकार "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" प्रारंभ करने जा रही है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1-1 हजार रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इस राशि का उपयोग महिलाएँ अपने परिवार को स्वावलंबी बनाने में कर सकेंगी।

27. प्रदेश की बेटियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण में सरकार ने एक नया इतिहास रच दिया है। अब से लगभग 16 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना में लखपति लाड़लियों की संख्या 44 लाख 39 हजार से भी अधिक हो चुकी है।

बेटियाँ खूब पढ़ें-लिखें और आगे बढ़ें, इस दृष्टि से उनकी उच्च शिक्षा के लिए 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के संशोधित स्वरूप के अंतर्गत किया गया है। प्रदेश के हर जिले में लाड़ली लक्ष्मी पथ, लाड़ली लक्ष्मी पार्क और लाड़ली लक्ष्मी वाटिकाएँ विकसित की जा रही हैं। प्रतिवर्ष 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक 33 लाख से अधिक हितग्राहियों को 1 हजार 466 करोड़ रुपए से अधिक का हितलाभ दिया जा चुका है।

28. मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष, महिला उद्यम शक्ति योजना तथा महिला इण्डस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना जैसी अभिनव पहलों के माध्यम से मेरी सरकार महिला सशक्तीकरण को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। महिला स्व-सहायता समूहों के 47 लाख से अधिक सदस्यों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में कामयाबी के झण्डे गाड़े हैं। सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों को न केवल 5 हजार 84 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिलाया है, बल्कि 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का भी निर्णय लिया है।

आजीविका मार्ट पोर्टल पर समूहों के 7 हजार से अधिक उत्पाद अपलोड किए गए हैं और अब तक 562 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का विक्रय हो चुका है।

29. मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश में अति गंभीर कुपोषण 9.2% से घटकर 6.5% रह गया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के माध्यम से मेरी सरकार ने पात्र बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार की जिम्मेदारी एक अभिभावक की तरह ली है। चाइल्ड बजट बनाने की पहल करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।

30. मेरी सरकार शिक्षा के प्रकाश को घर-घर तक पहुँचा रही है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17 वें स्थान से सीधे 5 वें स्थान पर पहुँचना मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। स्कूली बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 370 सी.एम. राईज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। इन स्कूलों को सर्वसुविधा संपन्न बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 6 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 91 हजार 498 विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु 25 हजार प्रति विद्यार्थी के मान से 228 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भुगतान की गई है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति कर सरकार युवाओं के उच्च शिक्षा के सपनों की उड़ान में पंख लगा रही है। योजना में अब तक 3 लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 1 हजार 21 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। सुपर 100 योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर 600 से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में सरकार ने 17 हजार शिक्षकों की भर्ती की है और 29 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही जारी है। ई-रूपी टोकन के माध्यम से स्कूली बच्चों को साइकिल प्रदाय की योजना मेरी सरकार की एक अभिनव पहल है।

31. मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को फलीभूत करने की दिशा में परिणाममूलक कार्य कर रही है। प्रदेश के चिन्हित मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक कॉलेजों में हिन्दी भाषा में पढ़ाई ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है।

प्रदेश में 12 नए शासकीय महाविद्यालय और 8 नए आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। गॉव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख 66 हजार से अधिक छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। सिंगरौली में खनिज अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

32. मेरी सरकार ने कौशल विकास, शिक्षा तथा रोज़गार को समेकित कर एक नई दिशा दी है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में लगभग 6 हजार प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्व-रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ करने का लक्ष्य है। 10 मॉडल संभागीय आई.टी.आई. में 32 प्रमुख ट्रेड्स में हर वर्ष लगभग 12 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष- 2022 में 24 नए आई.टी.आई. की स्थापना एवं भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिन पर लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

- मेरी सरकार ने स्व-रोज़गार के अवसरों को बड़े पैमाने पर सृजित कर इसे लाखों युवाओं के लिए भविष्य निर्माण का सबसे प्रभावी अस्त्र बना दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्व-निधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, संत रविदास स्व-रोज़गार योजना, भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोज़गार योजना, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन (शहरी एवं ग्रामीण),टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना एवं स्व-रोज़गार योजना, मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्व-रोज़गार योजना आदि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश की जनशक्ति, उद्यम शक्ति में परिवर्तित हो रही है। रोज़गार-दिवस के माध्यम से विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं के अंतर्गत 46 लाख 58 हजार से अधिक स्व-रोज़गार के नए अवसर सृजित कर 30 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

33. माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 लाख सरकारी रोज़गार के सृजन के संकल्प को साकार करते हुए मेरी सरकार ने प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लक्ष्य की ओर तेज गति से कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 81 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। नव चयनित पुलिस आरक्षकों को गरिमामय समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।

34. मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को विकास की गतिविधियों में सहभागी बनाने और सुशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ कर सभी जिलों में सी.एम. फेलो की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री युवा इण्टर्नशिप योजना के माध्यम से प्रदेश में 4 हजार 600 से अधिक युवा इण्टर्न को विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षण सत्र 2022-23 में लगभग 23 हजार छात्र-छात्राएँ सामाजिक उत्थान के लिये सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार हो रहे हैं।

35. प्रदेश का हर नागरिक निरोगी रहे और यदि किसी कारण से बीमार हो तो उसे सही समय पर सही उपचार मिले, यही मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान अंतर्गत जिलों को 146 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। सरकारी अस्पतालों में 530 प्रकार की औषधियाँ नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं। शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस, सीटी स्केन और 132 प्रकार की जाँच सुविधा मिल रही हैं। मध्यप्रदेश, 3 करोड़ 53 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 24 लाख 68 हजार से अधिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा चुका है।

36. प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं एवं 12 नए कॉलेज की स्थापना की जा रही है। भोपाल तथा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की बिस्तर क्षमता को कुल 2 हजार 500 बिस्तर तक बढ़ा दिया गया है। गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों को बीमारियों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत-निरामयम् मध्यप्रदेश योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

37. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में 362 आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा 200 और सेंटर्स जुलाई 2023 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है। सभी जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना की जा रही है। देवारण्य योजना औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती में एक नयी क्रांति का संचार कर रही है।

38. मेरी सरकार द्वारा विद्युत एवं बैटरी चलित ई-रिक्शा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में नए ड्रायविंग ट्रेनिंग सेन्टर और 3 स्थानों पर रीजनल ड्रायविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किए जा रहे हैं।

39. प्रदेश की 3 जेलों में आई.टी.आई. संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 500 बंदी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश जेल कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन कर औद्योगिक इकाइयों के संचालन और विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

40. मेरी सरकार करदाताओं को प्रोत्साहित करने और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होकर प्रयास कर रही है। करदाताओं की सुविधा के लिए हिन्दी चैटबोट "मेघा" लांच किया गया है। भामाशाह पुरस्कार वितरित कर करदाताओं एवं व्यवसायियों का उत्साहवर्द्धन किया गया है। आम-जनता में बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए "मध्यप्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना" प्रारंभ की जा रही है। चिन्हित दस्तावेजों के GIS आधारित फेसलेस ऑनलाईन पंजीयन के लिए उन्नत तकनीक पर आधारित साफ्टवेयर "संपदा-2.0" को आगामी वित्तीय वर्ष में लाईव करने का लक्ष्य है।

41. मेरी सरकार का यदि कोई सबसे प्रमुख राजधर्म है तो वह है सुशासन। यही जन-कल्याण की भी नींव है और विकास की भी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समाधान-एक दिन, सीएम हेल्पलाईन, महिला हेल्पलाईन, दिव्यांगजन हेल्पलाईन, सी.एम. जनसेवा, सेवाओं का डीम्ड अप्रूवल, वाट्सएप चैटबोट, सीएम-डैशबोर्ड, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, समाधान ऑनलाईन, साइबर तहसील, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर, ड्रोन्स का उपयोग, प्रगति ऑनलाईन,

मिशन कर्मयोगी, सिंगल सिटिजन डेटाबेस, सिंगल सर्विस डिलेवरी गेटवे और डायल-100 जैसी अनेकानेक योजनाओं और नवाचारों ने मध्यप्रदेश को सुशासन के क्षेत्र में देश के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। मध्यप्रदेश की नई विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की जाकर इस क्षेत्र में जिज्ञासा, अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने का ईको-सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

42. मेरी सरकार द्वारा दिनांक 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर-2022 तक संचालित किये गये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान ने हर पात्र हितग्राही को हितग्राहीमूलक योजना का लाभ दिलाने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। चिन्हित 38 हितग्राहीमूलक योजनाओं में 83 लाख से अधिक नए हितग्राहियों का जुड़ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मेरी सरकार न तो किसी पात्र हितग्राही को लाभ मिलने से वंचित रहने देगी और न ही अंतिम पंक्ति के अंतिम हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिलने तक चैन की साँस लेगी।

43. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हर प्रकार के माफिया के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्यवाही ने माफिया की कमर तोड़ दी है। मेरी सरकार ने 23 हजार एकड़ से अधिक भूमि को भू-माफिया से छुड़ाकर सुराज कॉलोनियों के निर्माण का संकल्प लिया है।

पहली बार 1 वर्ष में 6 नक्सलियों को मार गिराकर मध्यप्रदेश पुलिस ने देशभक्ति और जनसेवा का नया प्रतिमान स्थापित किया है। प्रदेश के सभी महिला थानों को मानव तस्करी रोधी इकाई भी घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है जहाँ पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु ऑनलाईन पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित किया गया। भोपाल में 50 बिस्तरीय पुलिस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।

44. मेरी सरकार मध्यप्रदेश के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गौरव को देश और दुनिया में प्रतिष्ठित करने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण इस दिशा में रचा गया एक अभूतपूर्व अध्याय है। श्री महाकाल महालोक परिसर के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य भी समय-सीमा में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। महाशिवरात्रि के अवसर पर "शिव ज्योति अर्पणम्-2023" आयोजन में जनता की भागीदारी से बाबा महाकाल की पावन धरा पर 18 लाख 82 हजार से अधिक दीपों को प्रज्ज्वलित करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है।

45. आदि गुरू शंकराचार्य की दीक्षा-स्थली ओंकारेश्वर में अद्वैत-धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदि गुरू की 108 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान तथा अद्वैत वन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। सरकार ने ओरछा में भव्य रामराजा लोक एवं चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक के निर्माण का भी निर्णय लिया है। भोपाल स्थित इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किये जाने से यहाँ का पुराना गौरव पुन: लौट आया है। मेरी सरकार प्रदेश के अनेक पवित्र और प्रसिद्ध धर्म-स्थानों का जीर्णोद्धार, विस्तार एवं विकास कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना पुन: प्रारंभ कर दी गई है। मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हवाई-जहाज से तीर्थ-यात्रा का सपना भी साकार करने जा रही है।

46. प्रदेश में सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सामाजिक -आध्यात्मिक संगठनों की क्षमताओं का सदुपयोग जन-कल्याण के कार्यों में करने की एक अभिनव पहल की है। बच्चों के लिए पौष्टिक मध्यान्ह भोजन, गौ-अभयारण्य का संचालन, रीयूजेबल सेनेटरी पैड्स निर्माण, जनजातीय आवासीय विद्यालयों का संचालन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन, खेल, प्राकृतिक चिकित्सा, योग,

ध्यान, भारतीय चिकित्सा पद्धति, वृक्षारोपण जैसे प्रकल्पों में इन संस्थानों की भागीदारी कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी साबित हो रही है। इसी प्रकार अंकुर कार्यक्रम, ऊर्जा साक्षरता अभियान, एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, ग्राम/नगर गौरव दिवस आयोजन एवं स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में जनता की बड़े पैमाने पर भागीदारी ने सरकार और समाज की शक्ति को मिलाकर विकास का एक नया मॉडल खड़ा कर दिया है।

47. मेरी सरकार नागरिकों के जीवन को तनावमुक्त और आनन्दमय बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन-कीर्तन, नाटक तथा खेलकूद की गतिविधियों से परिपूर्ण आनन्द उत्सव प्रदेश में इस वर्ष 8 हजार 500 से अधिक स्थानों पर मनाया गया है।

48. मेरी सरकार ग्रामोदय और नगरोदय की अवधारणा को सार्थक कर रही है। इन्दौर स्वच्छता में लगातार 6 बार से देश भर में अपना परचम लहरा रहा है। मध्यप्रदेश, देश का एकमात्र राज्य है, जिसके दो शहर - इन्दौर और भोपाल वाटर प्लस प्रमाणित है।

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी-2.0 एवं अमृत-2.0 मिलाकर 16 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अगले 5 वर्षों में करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 5 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक की सीवेज परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों एवं इन्दौर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन्दौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष-2023 के अंत तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में कॉलोनियों की विकास प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों को वैधानिक दर्जा देने की कार्यवाही की गई है।

49. मेरी सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य 3 हजार 900 से कहीं अधिक 5 हजार 372 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इनमें से 450 करोड़ रुपए की लागत के 2 हजार 648 अमृत सरोवर निर्मित हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप 3 करोड़ घनमीटर की जल भराव क्षमता विकसित हो गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) -2022 के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में प्रदेश को, देश में पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ ग्रामीण संपर्कता के लक्ष्य के 99 प्रतिशत से अधिक सड़कों का निर्माण कर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी है।

50. ग्रामीण पर्यटन, जवाबदेह पर्यटन, साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, विरासत पर्यटन, फिल्म पर्यटन आदि सभी प्रमुख क्षेत्रों में मध्यप्रदेश, देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल राज्यों की श्रेणी में अग्रणी है। हस्तशिल्प और हथकरघा आधारित प्रदेश का पहला पर्यटन-स्थल प्राणपुर, चंदेरी में प्रारंभ किया जा रहा है।

51. मध्यप्रदेश के कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पुनर्स्थापना विश्व के वन्य-प्राणी इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज हो गई है। प्रथम चरण में 8 और द्वितीय चरण में आए 12 चीतों के पुनर्स्थापन ने मध्यप्रदेश की जैव विविधता को समृद्धि के नए शिखर पर पहुँचा दिया है।

52. मेरी सरकार वनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन के अंतर्गत लगभग 8 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बाँस वृक्षारोपण कराया गया है। प्रदेश के 43 वन-धन केन्द्रों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है।

वन समितियों को काष्ठ राजस्व के शुद्ध लाभ का लाभांश 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी माह तेन्दूपत्ता संग्रहण समितियों को कुल 234 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

53. माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में देश में खेलों का लोकव्यापीकरण भी हो रहा है और नई खेल संस्कृति का विकास भी।मेरी सरकार ने खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाएँ और सम्मान देते हुए खेलों को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। मध्यप्रदेश को खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2022 के आयोजन का सौभाग्य मिला। इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 39 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए सबका दिल जीत लिया।खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से प्रदेश में खेल के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसी प्रतिष्ठित खेल स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण प्रदान करने, खेल अधोसंरचना विकास और खेलों को आम-जनता के जीवन का अंग बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करती रहेगी।

54. माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में आज विश्व के सभी मंचों पर भारत की एक अलग आवाज और एक अलग पहचान निर्मित हो रही है। मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में अपना श्रेष्ठतम योगदान देने के लिये संकल्पित है। समस्याओं को हल करने की शक्ति और संभावनाओं पर पहल करने की इच्छा-शक्ति से सरकार आपदा को भी अवसर में बदलने में समर्थ हुई है। प्रदेश के जन-जन का सहयोग, विश्वास, स्नेह एवं भागीदारी ही सरकार के संचालन का शक्ति-पुंज है।

55. आइए, हम सब मिलकर इक्कीसवीं सदी के विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में तन-मन-धन से जुट जाएँ।

जयहिन्द - जय मध्यप्रदेश

11.36 बजे

(माननीय राज्यपाल महोदय का सदन से चल समारोह के साथ प्रस्थान हुआ.)

11.39 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण के शेष समस्त पैराग्राफ पढे हुये माने जाना

अध्यक्ष महोदय -- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढे गये हैं. शेष समस्त पैराग्राफ पढे हुये माने जायेंगे तथा अभिभाषण पटल पर रखा गया माना जायेगा.

11.40 बजे **राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव**

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं".

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं".

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए, मैं, दिनांक 28 फरवरी एवं 02 मार्च, 2023 नियत करता हूँ.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 27 फरवरी, 2023 को सायंकाल 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं.

11.41 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

विधान सभा भवन के द्वार क्रमांक 4 के सामने माननीय सदस्यों का सामूहिक छायाचित्र

अध्यक्ष महोदय -- आज विधान सभा भवन के द्वार क्रमांक 4 के सामने माननीय सदस्यों का सामूहिक छायाचित्र लिया जाएगा. अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि छायाचित्र हेतु उक्त स्थल पर पहुँचने का कष्ट करें.

विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित.

पूर्वाह्न 11.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (9 फाल्गुन, शक संवत् 1944) को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,

भोपाल, प्रमुख सचिव

दिनांक 27 फरवरी, 2023 मध्यप्रदेश विधान सभा